गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 161
दि. 10.10.2025,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

सेमीकंडक्टर हब बना गुजरात

गाजा में शांति का नया सवेरा इतिहास का मोड़ जहाँ युद्ध थमने लगा

(जीएनएस)। गाजा की धरती, जो वर्षों से आग और आंसुओं की लकीरों से जलती रही, अब पहली बार उम्मीद की ठंडी हवा महसूस कर रही है। दो साल से अधिक समय तक चला खूनी संघर्ष — जिसमें निर्दोष बच्चों की चीखें, ढहती इमारतें और बारूद की गंध आम बात हो गई थी — अब उस बिंदु पर पहुंच गया है, जहाँ शायद इतिहास करवट ले रहा है। इज़राइल और हमास, जो एक-दूसरे को मिटाने की शपथ ले चुके थे, अब शांति की ओर पहला कदम बढ़ा चुके हैं। और इस चमत्कार के सूत्रधार हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप।

ट्रंप ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया मंच 'ट्रुथ' पर यह घोषणा की — "मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि इज़राइल और हमास ने हमारी शांति योजना के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब सभी बंधकों को जल्द रिहा किया जाएगा और इज़राइल अपने सैनिकों को पीछे बुलाएगा। यह एक मजबूत, स्थायी और शाश्वत शांति की दिशा में पहला कदम है।"

उनके शब्द केवल एक राजनयिक बयान नहीं थे, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए आशा की किरण थे जिन्होंने सालों से केवल युद्ध देखा था।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह समझौता किसी "चमत्कार" से कम नहीं। अमेरिकी राजनयिक आरोन

डेविड मिलर, जो बीस वर्षों तक मध्य पूर्व में शांति वार्ताओं से जुड़े रहे, कहते हैं — "यह डील सूरज, चाँद और तारे एक साथ आने जैसी घटना है। इतने सारे विरोधाभासों, दबावों और इतिहास की कड़वाहटों के बीच यह सहमति असंभव सी थी। पर अब यह हो गया।" मिलर बताते हैं कि हमास की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। दो वर्षों के युद्ध ने उसे भीतर से तोड़ दिया है। उसके कई शीर्ष नेता मारे जा चुके हैं, और जो बचे हैं वे भी जनसमर्थन खो चुके हैं। संगठन की आंतरिक संरचना कमजोर हो गई है। सिनवार की मौत के बाद हमास में एक दिशा का अभाव दिखा। उनके पास विकल्प नहीं बचे — युद्ध जारी रखने का अर्थ पूर्ण विनाश था, और यही विवशता उन्हें समझौते की ओर ले गई। लेकिन केवल हमास की कमजोरी ही नहीं, अरब देशों का एकजुट होना भी निर्णायक साबित हुआ। कतर, तुर्की और मिस्र ने हमास पर अभूतपूर्व दबाव बनाया कि वह बंधकों को रिहा करे और शांति वार्ता में शामिल हो। अरब राष्ट्रों ने यह भी संकेत दिया कि यदि हमास ने सहयोग नहीं किया, तो उसे क्षेत्रीय समर्थन से वंचित कर दिया जाएगा। वर्षों बाद अरब विश्व ने इस मुद्दे पर एक साझा रुख अपनाया — और यही एकता हमास को झुकाने में सफल रही।

इस बीच, डोनाल्ड ट्रंप का रोल अप्रत्याशित रूप से निर्णायक रहा। मिलर कहते हैं, "इतिहास में शायद यह पहली बार हुआ कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर इतना प्रत्यक्ष दबाव डाला हो। ट्रंप ने स्पष्ट कहा कि अगर इज़राइल शांति की ओर नहीं बढ़ेगा, तो अमेरिका भी अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करेगा।" यह अमेरिकी नीति में एक ऐतिहासिक बदलाव था — क्योंकि अमेरिका सदैव इज़राइल का अडिग समर्थक रहा है। नेतन्याहू, जो अब तक हर शर्त पर अड़े रहते थे, ट्रंप के कड़े रुख के आगे नरम पड़े।

अब सवाल यह है कि यह "पहला चरण" वास्तव में क्या लेकर आया है? समझौते के तहत चार मुख्य बिंदु तय हुए हैं —

पहला, हमास गाजा में रखे सभी इज़राइली बंधकों को रिहा करेगा, जिनमें लगभग 50 लोग शामिल हैं। यह कदम दोनों पक्षों के बीच विश्वास बहाली का सबसे बड़ा संकेत माना जा रहा है। दूसरा, इज़राइल 24 घंटे के भीतर अपनी सेना को तय सीमा तक पीछे हटाएगा। इससे गाजा में दशकों बाद शांति की पहली सांस ली जा सकेगी।

तीसरा, इज़राइल लगभग 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा — यह हमास की मुख्य मांग थी, जिसे अब मान लिया गया है। चौथा, गाजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति को बढ़ाया जाएगा — भोजन, दवाइयाँ और पुनर्निर्माण सामग्री अब बिना बाधा पहुंच सकेगी।

इन चार बिंदुओं के सफल क्रियान्वयन के बाद दूसरा चरण शुरू होगा, जिसमें स्थायी युद्धविराम, हमास के हथियारों का नियंत्रण और गाजा के भविष्य की शासन संरचना पर चर्चा होगी। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से अपील की है कि वे समझौते की शर्तों का सम्मान करें और शांति के इस अवसर को व्यर्थ न जाने दें।

गाजा की जनता, जिसने वर्षों तक केवल ध्वंस देखा, अब एक नए सवेरा की प्रतीक्षा कर रही है। एक बुजुर्ग फिलिस्तीनी महिला ने मीडिया से कहा — "हमने इतने लंबे समय तक केवल मौत देखी। अगर अब थोड़ा भी सुकून मिले, तो यही हमारी जीत है।"

यह समझौता केवल दो देशों के बीच की शांति नहीं है; यह मानवता की वह जीत है, जो यह याद दिलाती है कि हर युद्ध के बाद भी संवाद की संभावना बची रहती है। जब बंदूकें थक जाती हैं, तो शब्द रास्ता बनाते हैं।

गाजा की रेत पर अब शायद फिर से बच्चे खेलेंगे, महिलाएँ बाजार जाएँगी, और रातें बम की नहीं, सितारों की रोशनी में बीतेंगी। यह नये युग की शुरुआत हो सकती है — एक ऐसा युग जहाँ शांति केवल सपना नहीं, बल्कि साकार हकीकत बने।

सरोगेसी कानून पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: 2022 से पहले फ्रीज भ्रूण वालों को मिली राहत

(जीएनएस)। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है, जिससे जनवरी 2022 से पहले भ्रूण फ्रीज कराने वाले दंपतियों को राहत मिली है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस कानून के तहत निर्धारित आयु सीमा उन दंपतियों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने कानून लागू होने से पहले सरोगेसी प्रक्रिया शुरू की थी। यह फैसला न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने तीन दंपतियों की याचिकाओं पर सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी दंपती ने सरोगेसी प्रक्रिया शुरू कर दी थी और उनके पास फ्रीज भ्रूण थे या वे भ्रूण को सरोगेट मां में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में थे, तो उनके ऊपर आयु प्रतिबंध लागू नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल क्लीनिक में जाने वाले जोड़े इस राहत के दायरे में नहीं आते।

कोर्ट ने कहा, "अगर सरोगेट बच्चा 2021 अधिनियम के पहले 10 महीनों में पैदा होता है, तो दंपति पर आयु प्रतिबंध लागू नहीं होगा।" इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अन्य दंपती जो इसी तरह की स्थिति में हैं, वे उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके इस राहत का लाभ उठा सकते हैं।

तीन दंपतियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, क्योंकि उनकी आयु महिला के लिए 50 वर्ष और पुरुष के लिए 55 वर्ष से अधिक हो गई थी, लेकिन उन्होंने 2021 के कानून लागू होने से पहले ही भ्रूण फ्रीज और स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।

सरोगेसी अधिनियम, 2021 के अनुसार, यह कानून 25 जनवरी 2022 से लागू हुआ। अधिनियम की धारा 4 (iii) (C) (I) में कहा गया है कि सरोगेसी से बच्चा पैदा करने के लिए इच्छुक दंपती विवाहित होना चाहिए, महिला की आयु 23-50 वर्ष और पुरुष की आयु 26-55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा को चुनौती देने वाले दंपतियों के पक्ष में राहत दी है।

इस फैसले से उन दंपतियों को बड़ा सहारा मिला है, जो कानूनी रूप से अब तक सरोगेसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से वंचित थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार यह तय नहीं कर सकती कि कौन माता-पिता बनेगा, और कानून की कसौटी पर दंपतियों को न्याय मिलने का मार्ग खुला है।

जम्मू-कश्मीर के कोकरनाग में पैरा-कमांडो का शव मिला, दूसरे जवान की तलाश जारी

(जीएनएस)। श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग क्षेत्र में एंटी-टेरर ऑपरेशन के दौरान लापता हुए एक पैरा-कमांडो का शव बरामद हुआ है। शव बैग और सर्विस वेपन के साथ मिला, जो सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन का हिस्सा था। अधिकारियों ने अभी मृतक जवान की पहचान आधिकारिक तौर पर साझा नहीं की है।

सेना और पुलिस की संयुक्त टीमें खराब मौसम और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद खोज ऑपरेशन में जुटी हैं। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से सर्च को तेज किया गया है ताकि दूसरे लापता जवान को भी सुरक्षित ढूंढा जा सके। जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले से दो भारतीय सैनिक सोमवार से लापता थे। दोनों जवान एलीट 5 पैरा फोर्स के सदस्य हैं और उनकी ड्यूटी कोकरनाग क्षेत्र के गदूल इलाके में लगी थी। खोज के दौरान सेना की टीमें लगातार स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में रही हैं और इलाके की कठोर भौगोलिक स्थिति के बावजूद अभियान जारी रखा जा रहा है।

अधिकारी बता रहे हैं कि शव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लापता जवान की तलाश पूरी ताकत के साथ जारी है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य न केवल दूसरे जवान को सुरक्षित ढूंढना है, बल्कि इलाके में सुरक्षा और आतंकवाद निरोधी कार्रवाई को भी सुनिश्चित करना है।

कर्नाटक सरकार का ऐतिहासिक फैसला — अब हर महीने महिलाओं को मिलेगा एक दिन का पेड पीरियड लीव

(जीएनएस)। बेंगलुरु से आई एक ऐतिहासिक खबर ने देशभर की कार्यरत महिलाओं को राहत और सम्मान दोनों दिया है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य, गरिमा और कार्यस्थल के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए "मासिक धर्म अवकाश नीति 2025" को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत सरकारी, निजी और औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाली प्रत्येक महिला को हर महीने एक दिन का पेड पीरियड लीव (वेतन सहित अवकाश) मिलेगा। यानी सालभर में कुल 12 अवकाश, जिनका वेतन में कोई कटौती नहीं होगी। यह फैसला मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। सरकार का कहना है कि इस नीति का उद्देश्य महिलाओं को मासिक धर्म के दिनों में आवश्यक आराम और शारीरिक-मानसिक राहत देना है, जिससे वे अपने कार्यक्षेत्र में और अधिक उत्पादक और आत्मविश्वास से भरी रहें।

श्रम मंत्री संतोष लाड ने इस नीति की घोषणा करते हुए कहा कि "यह सिर्फ एक अवकाश नहीं, बल्कि महिला स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता का प्रतीक है। लंबे समय से महिलाएं मासिक धर्म के दौरान काम के दबाव, असहजता और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करती रही हैं। अब यह नीति उनके सम्मान और स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक ठोस कदम है।"

इस नीति का प्रारूप एक 18 सदस्यीय समिति ने तैयार किया था, जिसकी अध्यक्षता क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की विधि विभाग प्रमुख डॉ. सपना एस. ने की थी। समिति ने विस्तृत अध्ययन के बाद सिफारिश दी कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के शरीर में हार्मोनल बदलाव, दर्द और थकान को देखते हुए उन्हें एक अतिरिक्त विश्राम दिवस मिलना चाहिए। समिति ने यह भी कहा कि इस पहल से समाज में मासिक धर्म को लेकर बनी झिझक और वर्जनाओं को तोड़ने में मदद मिलेगी।

सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह नीति सभी कार्यरत महिलाओं पर लागू होगी — चाहे वे सरकारी विभागों, निजी कंपनियों, या औद्योगिक इकाइयों में काम करती हों। नीति में यह भी प्रावधान है कि कोई भी नियोक्ता इस अवकाश के उपयोग को लेकर महिला कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा और इसे "मानव अधिकारों से जुड़ी बुनियादी सुविधा" के रूप में माना जाएगा। महिला संगठनों ने कर्नाटक सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे "भारत में महिला कार्यनीति के क्षेत्र में मील का पत्थर" बताया है। बेंगलुरु स्थित महिला कर्मचारी संगठन ने कहा कि "पीरियड लीव नीति से न केवल कार्यस्थल का वातावरण अधिक संवेदनशील बनेगा, बल्कि इससे महिलाओं के आत्मसम्मान को भी मजबूती मिलेगी।" इस फैसले के साथ कर्नाटक देश का ऐसा पहला दक्षिणी राज्य बन गया है, जिसने निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश को अनिवार्य किया है। इससे पहले केरल, बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों ने सीमित दायरे में ऐसी पहलें की थीं, लेकिन कर्नाटक का यह कदम सबसे व्यापक और व्यवस्थित नीति के रूप में देखा जा रहा है।

कैबिनेट बैठक में सरकार ने महिला कल्याण के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं। इनमें श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2025 की मंजूरी, 1000 करोड़ रुपये की लागत से राज्य के बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण, और कनकपुर में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना शामिल है। इसके अलावा मैसूर के सीपीसी पॉलिटेक्निक का जीर्णोद्धार, और 55 करोड़ की लागत की इको-टूरिज्म परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार ने उम्मीद जताई है कि यह निर्णय महिलाओं की कार्य क्षमता बढ़ाने के साथ ही उन्हें एक स्वस्थ, संतुलित और सम्मानजनक कार्यस्थल प्रदान करेगा।

विजय के घर पर झूठी बम धमकी से मचा हड़कंप, पुलिस ने रातभर की तलाशी के बाद आरोपी को किया गिरफ्तार

(जीएनएस)। चेन्नई। चेन्नई में गुरुवार की रात तब हड़कंप मच गया जब पुलिस नियंत्रण कक्ष में फोन आया कि अभिनेता और तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) प्रमुख विजय के नीलंकरई स्थित घर में बम लगाया गया है। इस सूचना के मिलते ही पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कुछ ही मिनटों में बम निरोधक दस्ता, स्थानीय पुलिस और फोरेंसिक विशेषज्ञ मौके पर पहुंच गए और देर रात से सुबह तक घर की तलाशी ली गई। हालांकि लंबी जांच के बाद यह सूचना फर्जी निकली। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, फोन करने वाले व्यक्ति की पहचान 37 वर्षीय शाबिक के रूप में हुई है। उसने देर रात नियंत्रण कक्ष को कॉल कर दावा किया था कि विजय के घर में बम लगाया गया है और जल्द ही विस्फोट होने वाला है। कॉल की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बिना समय गंवाए कार्रवाई की और रात करीब तीन बजे से तलाशी अभियान शुरू किया।

बम निरोधक दस्ते ने पहले विजय के घर के बाहर तलाशी शुरू की और आसपास के इलाके में सुरक्षा घेरा बना दिया गया। थोड़ी देर बाद जब अभिनेता विजय जागे, तो पुलिस को घर के अंदर तलाशी लेने की अनुमति दी गई। पुलिस और बम निरोधक टीम ने घर के हर हिस्से को बारीकी से खंगाला, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। अंततः सुबह साढ़े सात बजे तलाशी खत्म की गई और टीम ने राहत की सांस ली।

शुरुआती जांच में यह अफवाह पहले ईमेल धमकी से जुड़ी बताई गई थी, लेकिन बाद में यह स्पष्ट हुआ कि धमकी फोन कॉल के माध्यम से दी गई थी। पुलिस ने कॉल ट्रेसिंग के जरिए आरोपी तक पहुंच बनाई और उसे गिरफ्तार कर लिया।

चेन्नई पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि यह घटना शहर में पिछले कुछ महीनों में बढ़ रहे फर्जी धमकी मामलों का ही हिस्सा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हाल ही में कई जानी-मानी हस्तियों को हॉटमेल पते से बम धमकी वाले फर्जी ईमेल भेजे गए थे। पिछले महीने अभिनेता और राजनेता एस. शेखर को भी इसी तरह का ईमेल मिला था। इन ईमेलों की भाषा और सामग्री लगभग एक जैसी पाई गई है, जिससे यह संदेह गहराता जा रहा है कि इनके पीछे एक ही व्यक्ति या गिरोह काम कर रहा है। छह अक्टूबर को भी चेन्नई के एक प्रमुख राष्ट्रीय समाचार चैनल के कार्यालय में ईमेल से धमकी दी गई थी कि उनके परिसर में तीन आरडीएक्स बम लगाए गए हैं। उस मामले में भी बम निरोधक दस्ते ने पूरी तलाशी के बाद रिपोर्ट दी कि यह "झूठी धमकी" थी।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की फर्जी धमकियों से न केवल जनता में भय फैलता है, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों के संसाधनों का भारी नुकसान भी होता है। आरोपी शाबिक से पूछताछ जारी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने यह हरकत नशे की हालत में की थी या किसी और के इशारे पर।

चेन्नई पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे सोशल मीडिया या फोन के माध्यम से फैलाए जाने वाले किसी भी तरह के अफवाह या धमकी संदेशों पर ध्यान न दें और यदि ऐसी कोई सूचना मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि झूठी सूचना फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह के गैर-जिम्मेदाराना कृत्य की हिम्मत न कर सके।

तमिलनाडु की फिल्म और राजनीतिक दुनिया में विजय जैसी लोकप्रिय हस्ती को मिली यह झूठी धमकी इस बात का संकेत है कि डिजिटल युग में सुरक्षा एजेंसियों को अब तकनीकी स्तर पर और भी चौकस रहना होगा। पुलिस अब इस घटना के डिजिटल निशानों की फॉरेंसिक जांच कर रही है ताकि ऐसे साइबर अपराधियों की जड़ तक पहुंचा जा सके जो महज मज़ाक के नाम पर समाज में डर और अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं।

सीजेआई पर हमला: वकील की बार एसोसिएशन मेंबरशिप खत्म, सुप्रीम कोर्ट ने जताई गंभीर चिंता

(जीएनएस)। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने गुरुवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई पर हमले की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर (71) की मेंबरशिप तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दी। SCBA ने कहा कि वकील का यह कृत्य पेशेवर नैतिकता, शिष्टाचार और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का गंभीर उल्लंघन है।

CJI बीआर गवई ने कहा कि 6 अक्टूबर की घटना से वह और उनके साथी जज हैरान थे, लेकिन अब वह इसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। जस्टिस उज्जल भुइयां ने घटना को सुप्रीम कोर्ट के अपमान के रूप में वर्णित करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई होना आवश्यक है।

बेंगलुरु में ऑल इंडिया एडवोकेट एसोसिएशन ने राकेश किशोर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 132 और 133 के तहत मामला दर्ज किया। गौरतलब है कि CJI गवई ने व्यक्तिगत शिकायत दर्ज कराने से इनकार किया था।

घटना का संक्षेप इस प्रकार है: 6 अक्टूबर को राकेश किशोर ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। जूता CJI तक नहीं पहुँच सका। इस दौरान सुरक्षाकर्मियों ने वकील को तत्काल नियंत्रित कर बाहर किया। घटना के समय CJI की बेंच किसी मामले की सुनवाई कर रही थी। राकेश किशोर ने नारे भी लगाए, जिसमें उन्होंने कहा, "सनातन का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान।"

SCBA और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई इस बात को स्पष्ट करती है कि न्यायपालिका की गरिमा और अदालत की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। घटना ने वकीलों और नागरिकों दोनों को यह संदेश दिया कि कोर्ट में असभ्य या हिंसक कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाए जाएंगे।

संपादकीय

हादसों की सड़क

यह शर्मनाक ही है कि भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इन दुर्घटनाओं में अन्य कारणों के अलावा सबसे अधिक भूमिका तकनीकी व गुणवत्ता की खामियों वाली सड़कों की होती है। यह भयावह है कि वर्ष 2023 में देश में हुई पांच लाख दुर्घटनाओं में करीब पौने दो लाख लोगों की मौत हुई। उस पर सबसे दुखद यह है कि मरने वालों में एक लाख चौदह हजार लोग अट्ठारह से 45 वर्ष के बीच के युवा थे। जो परिवार के कमाने वाले व नई उम्मीद थे। इन हालात को देखते हुए ही केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक इन सड़क दुर्घटनाओं को आधा करने का लक्ष्य रखा है। यह विडंबना ही है कि दुर्घटनाएं रोकने के लिये सख्त कानून बनाने एवं तकनीक के जरिये चालकों की लापरवाही पर नजर रखने जैसे उपायों के बावजूद आशातीत परिणाम सामने नहीं आए हैं। ऐसे में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के बेबाक सुझाव से सहमत हुआ जा सकता है कि खराब सड़क निर्माण को गैर-जमानती अपराध बना दिया जाना चाहिए। इसके लिये ठेकेदार और इंजीनियर की जवाबदेही तय होनी चाहिए। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के एक कार्यक्रम में उन्होंने दुःख जताया कि विदेशों में होने वाले कार्यक्रमों में जब भारत में विश्व की सर्वाधिक सड़क दुर्घटना वाले देश के रूप में चर्चा होती है, तो उन्हें शर्म महसूस होती है। आखिर तमाम प्रयासों के बावजूद सड़क हादसे क्यों नहीं थम रहे हैं।

यह बात तय है कि अगले पांच सालों में सड़क दुर्घटनाओं को यदि आधा करना है, तो युद्ध स्तर पर प्रयास करने होंगे। उन कारणों को तलाशना होगा, जिनकी वजह से हर साल सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि होती है। आखिर क्या वजह है कि राजमार्गों के विस्तार और तेज गति के अनुकूल सड़कें बनने के बावजूद हादसे बढ़े हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि राजमार्गों व विभिन्न तीव्र गति वाली सड़कों में साम्य का अभाव है, वहीं मोड़ों को दुर्घटना मुक्त बनाने हेतु तकनीक में बदलाव की जरूरत है। ऐसे में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय को उन कारणों की पड़ताल करनी होगी, जो पर्याप्त धन आवंटन के बावजूद सड़कों को दुर्घटनामुक्त बनाने में बाधक हैं। ऐसे में जरूरी है कि सड़कों की निर्माण सामग्री और डिजाइनों की निगरानी के लिये स्वतंत्र व सशक्त तंत्र बनाया जाए, जो बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के काम कर सके। साथ ही मंत्रालय का दायित्व बनता है कि इस बाबत स्पष्ट नीति को सख्ती से लागू किया जाए। यह जानते हुए कि सड़कों के ठेके में मोटे मुनाफे के लिए एक समांतर भ्रष्ट तंत्र देश में विकसित हुआ है, जो निर्माण कार्य की गुणवत्ता से समझौता करने से परहेज नहीं करता। जिसके खिलाफ उठने वाली ईमानदार आवाजें दबा दी जाती हैं। निस्संदेह, गुणवत्ता का मूल्यांकन करने वाली व्यवस्था की जवाबदेही तय करने की सख्त जरूरत है। तब हमें यह सुनने को नहीं मिलेगा कि उद्घाटन के कुछ ही बाद ही सड़क उखड़ गई या बारिश में घुल गई।

सरकारी धन से चुनावी रेवड़ियां बांटने के खतरे

> चुनावी समय में सरकारों द्वारा नकद या मुफ्त सुविधाएं देकर वोट हासिल करने की प्रवृत्ति 'रेवड़ी संस्कृति' बन गई है, जो लोकतंत्र, वित्तीय अनुशासन और राजनीतिक नैतिकता को कमजोर करती है।

बिहार में चुनावों की तारीखें घोषित होने के साथ ही 'राजनीतिक रिश्वतखोरी' की बातें चलने लगी हैं। राजनीतिक रिश्वतखोरी यानी मतदाता को रेवड़िया बांटकर उन्हें अपने पक्ष में वोट देने के लिए लुभाना। कहा यह भी जा रहा है कि चलो अब कुछ दिन रेवड़ियां बांटने की घोषणाओं से तो पीछा छूटेगा। यहां रेवड़ियों का मतलब वह 'मुफ्त की सेवाएं' हैं जिनका लालच देकर राजनेता मतदाता को बरगलाते हैं। पहले बिजली-पानी जैसी जीवनोपयोगी चीज़ें मतदाता को दी जाती थीं, देने का वादा किया जाता था, और अब तो यह नकद पैसा बांटा जा रहा है। बिहार सरकार ने कुछ ही दिन पहले एक करोड़ से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में दस हज़ार रुपये जमा करवा कर इस रेवड़ी संस्कृति को एक नया आयाम दे दिया है। एक करोड़ महिलाओं का मतलब एक करोड़ परिवारों तक पहुंचना है। महिलाओं के सशक्तीकरण के नाम पर यह सीधी रिश्वत है।

सवाल यह पूछा जा रहा है कि किसी सरकार द्वारा इस तरह की नकद राशि बांटना क्या सरकार के पैसों से चुनाव जीतना नहीं है? यदि ऐसा है तो फिर इसे अपराध की श्रेणी में क्यों न रखा जाये, और यदि यह अपराध है तो फिर इसकी कोई सज़ा तय क्यों नहीं होनी चाहिए? पूछा तो यह भी गया है कि सरकार द्वारा मुफ्त राशन बांटना भी क्या एक तरह से रेवड़ी बांटना नहीं है?

आश्वासन वाली राजनीति कोई नयी चीज नहीं है। और ऊपरी तौर पर देखें तो यह उतनी ग़लत भी नहीं लगती। आखिर जनता के हित की बात सोचना सरकार का काम है, और जनता को वित्तीय सहायता देकर जनता की सहायता ही

तो की जाती है। पर सवाल उठता है कि जनता की यह 'मदद' सरकारों और राजनीतिक दलों को चुनावों से पहले ही याद क्यों आती है? सवाल यह भी उठाना चाहिए कि राजनीति में 'तोहफे' बांटने की यह परंपरा अपराध की श्रेणी में क्यों नहीं आनी चाहिए?

चुनाव से कुछ अरसा पहले, या वैसे भी, हमारी सरकारें जनता की मदद की घोषणाएं शुरू कर देती हैं और मीडिया में इसे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के तोहफे के रूप में प्रचारित किया जाता है। कुछ ही साल पहले चुनाव-प्रचार के दौरान स्वयं प्रधानमंत्री ने बिहार में खुले आम तोहफों की बोली लगायी थी। एक चुनाव-सभा में उन्होंने कुछ ऐसा कहा था, 'कितने दूं, दस करोड़?, सौ करोड़?, हजार करोड़? या लाख करोड़?' उनकी घोषणा पर श्रोताओं ने तालियां बजाकर इसका स्वागत किया था, निश्चित रूप से इस तोहफे का कुछ असर चुनाव परिणाम पर भी पड़ा होगा। पर चुनावी लाभ के लिए जनता के पैसों के तोहफे इस तरह बांटने की घोषणा क्या विद्रूप पहल नहीं मानी जानी चाहिए? सच तो यह है कि इसे तोहफा या उपहार कहना ही ग़लत है। यह अनुचित आर्थिक लेन-देन ही है– और रिश्वत देना या लेना दोनों अपराध हैं! इस अपराध की सज़ा क्यों तय नहीं होती? इस सवाल का सीधा-सा जवाब यह है कि यह अपराध सबकी मिली-भगत से हो रहा है। राजनेताओं को, सरकारों को, राजनीतिक दलों को रेवड़ियां बांटने, या कहना चाहिए रिश्वत देकर अपना काम निकालने का यह एक आसान तरीका लगता है। ऐसे में पारस्परिक लाभ के इस सौदे में भला किसी को कुछ ग़लत क्यों लगेगा?

पर यह ग़लत परंपरा है जन-कल्याण की योजनाएं बनाना, उन्हें ईमानदारी के साथ क्रियान्वित करना सरकारों का काम है। पर यह काम चुनावों से ठीक पहले ही क्यों? एक करोड़ महिलाओं को बिहार की नीतीश सरकार द्वारा दस हज़ार रुपये देने और विपक्ष द्वारा पच्चीस सौ रुपये प्रति माह देने का वादा करने में कोई विशेष अंतर नहीं है। कहा जा सकता है कि इस तरह की घोषणाएं वर्तमान या भावी सरकार की रीति-नीति बताती हैं, पर बताने की यह आवश्यकता चुनावों के समय पर ही किसी को याद क्यों आती है?

ऐसा नहीं है कि इस तरह के सवाल पहले कभी उठे नहीं हैं। उठते रहे हैं ये सवाल, पर राजनीतिक नफा-नुकसान का गणित इन सवालों को उठाने वाली नैतिकता पर अक्सर हावी हो जाता है। कभी महिला मतदाताओं को साड़ियां बांटकर तमिलनाडु की जयललिता ने वोट के लिए रिश्वत की इस परंपरा की शुरुआत की थी। द्रमुक के ही करुणानिधि ने दो रुपये किलो चावल बांटकर इस शुरुआत को चुनाव जीतने की एक कला के रूप में विकसित किया। फिर तो जैसे देश के अलग-अलग हिस्सों में इस कला को निखारने की एक प्रतिस्पर्धा ही चल पड़ी। ऐसा भी नहीं है कि इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की ज़रूरत की ओर किसी का ध्यान न गया हो। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने इस 'रेवड़ी संस्कृति' को मुद्दा बनाया था। पर जल्दी ही उन्हें यह अहसास हो गया कि यह संस्कृति तो स्वयं उनके लिए भी लाभदायक है और वे भी लाभ लुटाकर लाभ कमाने की इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गये।

अब तो हमारे राजनीतिक दल यह सोचना भी नहीं चाहते कि इस प्रतियोगिता में राज्यों का बजट घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है—यह घाटा खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। यही सब देखते हुए यह मांग भी उठी थी कि मुफ्त संस्कृति वाली इस राजनीति के वित्तीय अनुशासन के बारे में भी कुछ नियम-कायदे बनने चाहिए। कहा यह भी गया कि चुनाव घोषणापत्रों में ऐसी युक्तियों-योजनाओं के साथ उन पर होने वाले व्यय का ब्योरा भी दिया जाना चाहिए, यह भी बताया जाना चाहिए कि इन योजनाओं पर होने वाले खर्च की व्यवस्था कैसे होगी। इस संदर्भ में रसोई घर की मुफ्त सिलेंडर वाली योजना के हश्र की बात भुलाई नहीं जानी चाहिए। इस बात का भी लेखा-जोखा होना चाहिए कि मुफ्त सिलेंडर कैसे मिलेंगे और कैसे मिलते रह सकेंगे। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। होता दिख भी नहीं रहा।

यहां यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि उच्चतम न्यायालय ने भी इस संदर्भ में हस्तक्षेप किया था। न्यायालय ने तो यह भी कहा था कि राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों में ऐसी योजनाओं की घोषणा को किसी तरह की कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए। पर, जो होना चाहिए, और जो हो रहा है, हमारी राजनीति में उसमें बहुत अंतर है। यह अंतर कब और कैसे पटेगा, पता नहीं। लेकिन यह तय है कि हमारे राजनेता इस बारे में लगातार सक्रिय हैं कि यह अंतर मिटाने की बात ही न हो। वे मानते हैं कि जनता की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। इसलिए, राजनीति की रेवड़ी संस्कृति के बारे में कभी-कभार बात तो कर ली जाती है, पर इस संस्कृति के खतरों से बचने की आवश्यकता किसी को महसूस नहीं होती।

राजनीतिक नैतिकता का तकाज़ा है की राजनीति की यह घटिया संस्कृति समाप्त हो, पर राजनीतिक आवश्यकता इस नैतिकता को कहीं पीछे छोड़ देती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर हमारे नेता तो यह भी जानते हैं कि चुनाव की आदर्श आचार संहिता का मजाक कैसे उड़ाया जा सकता है–बिहार में चुनावों की तारीख की घोषणा के ठीक पहले मेट्रो लाइन के उद्घाटन का लालच मुख्यमंत्री छोड़ नहीं पाये। सुना है, यह लाइन अभी पूरी तरह तैयार भी नहीं है! स्पष्ट है, राजनीतिक स्वार्थ किसी भी अनुशासन को स्वीकार नहीं करते।

प्रेरणा

शब्दों से गूंजता मौन

जीवन में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो कम बोलते हैं पर उनका मौन ही इतना गूंजता है कि उनके शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती। अमेरिका के 30वें राष्ट्रपति कॉल्विन कूलिज भी ऐसे ही व्यक्ति थे। उनका जीवन इस सत्य का प्रमाण था कि गहराई शब्दों में नहीं, बल्कि मौन में बसती है। वे न बोलने में विश्वास रखते थे, क्योंकि उनके लिए मौन ही मन की स्पष्टता और आत्मसंयम का प्रतीक था।

कूलिज का स्वभाव अत्यंत मितभाषी था। वे अपने कार्यों में इतने तल्लीन रहते थे कि अनावश्यक वार्तालाप उन्हें व्यर्थ लगता था। उनकी पत्नी ग्रेस कूलिज अक्सर इस बात से खिन्न हो जाया करती थीं। उन्हें लगता था कि राष्ट्रपति का इतना मौन रहना एक तरह का अजीबपन है। एक बार रविवार की सुबह दोनों पति-पत्नी साथ में चर्च गए। पादरी साहब ने "पाप" विषय पर प्रवचन दिया। प्रवचन समाप्त होने के बाद वे दोनों घर लौट रहे थे। रास्ते में पत्नी ने बातचीत का आरंभ करने के लिए मुस्कराकर पूछा —

"क्या आपने आज का प्रवचन सुना?"

कूलिज ने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया — "हाँ।"

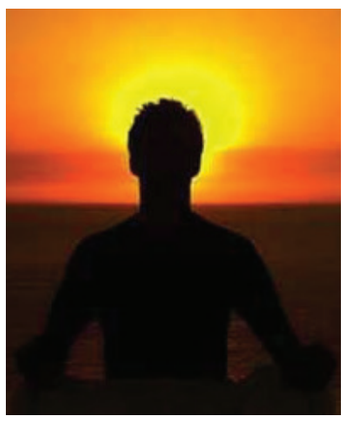

पत्नी को लगा कि अब वे शायद कुछ और कहेंगे, परंतु वे फिर मौन हो गए। कुछ क्षण के मौन के बाद उन्होंने फिर पूछा —

"तो बताइए, प्रवचन का विषय क्या था?"

कूलिज ने उसी सहजता से कहा — "पाप।"

अब पत्नी को कुछ जिज्ञासा हुई। उन्होंने तीसरा प्रश्न किया —

"ठीक है, लेकिन पादरी इस विषय में क्या कह रहे थे?"

कूलिज ने उसी नपे-तुले स्वर में उत्तर दिया —

"वह इसके विरोध में थे।"

यह सुनकर ग्रेस कुछ क्षण चुप रहीं। फिर उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी। उन्होंने देखा कि उनके पति के उत्तर छोटे अवश्य हैं, लेकिन उनमें पूर्ण अर्थ छिपा है। वे केवल "पाप" के विरोध की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि जीवन की उस सादगी की भी ओर संकेत कर रहे थे, जिसमें सत्य को सरल शब्दों में कहा जा सकता है।

कॉल्विन कूलिज का यह प्रसंग उनके मौन की शक्ति को प्रकट करता है। मौन का अर्थ उदासीनता नहीं, बल्कि विचारों की गहराई है। वे व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान होते हैं, जो कम बोलकर भी बहुत कुछ कह देते हैं। यह मौन ही उन्हें भीतर से दृढ़ बनाता है, और जब वे बोलते हैं, तो उनके शब्दों में तीव्रता, गंभीरता और प्रभाव अपने आप उतर आता है।

आज के समय में, जब संवाद शोर बन चुका है, लोग एक-दूसरे पर शब्दों की बौछार करते हैं, वहाँ कूलिज जैसा मौन व्यक्ति हमें यह सिखाता है कि हर विचार को शब्दों में ढालना आवश्यक नहीं होता। कभी-कभी मौन ही सबसे सशक्त वक्तव्य बन जाता है।

मौन व्यक्ति अपने भीतर एक संसार बसाता है, जहाँ विचारों की ध्वनि स्पष्ट होती है, और आत्मा की आवाज़ सबसे अधिक सुनाई देती है। वह समझता है कि शब्द अक्सर भ्रम पैदा करते हैं, जबकि मौन स्पष्टता लाता है।

कॉल्विन कूलिज का जीवन इस सत्य का उदाहरण है कि मौन कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल की पराकाष्ठा है। जो व्यक्ति अपने शब्दों को नियंत्रित कर सकता है, वही अपने मन और कर्मों को भी नियंत्रित कर सकता है। मौन व्यक्ति दूसरों से नहीं, स्वयं से संवाद करता है — और यही संवाद उसे महान बनाता है। उनकी पत्नी ने उस दिन शायद पहली बार समझा कि उनका पति केवल कम बोलने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसा आत्मसंयमी मनुष्य है, जो अपने भीतर पूर्ण स्थिरता लिए चलता है। और यही स्थिरता उसके नेतृत्व की सबसे बड़ी शक्ति थी।

जीवन के इस छोटे से प्रसंग में एक बहुत बड़ी सीख छिपी है — कि मनुष्य की गहराई उसके शब्दों की संख्या से नहीं, बल्कि उसके मौन की गुणवत्ता से मापी जाती है। मौन में वह शक्ति है जो शब्दों से परे है। मौन में सत्य छिपा है, और वही सत्य अंततः जीवन को अर्थ देता है।

Modi की मेहनत रंग लाई, Britain के लिए India अब सिर्फ बाजार नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदार बन गया है

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का भारत दौरा दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और शिक्षा क्षेत्रों में एक नई रणनीतिक गहराई का प्रतीक बन गया। स्टारमर ने अपने पहले दौरे पर मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और दोनों देशों ने संयुक्त रूप से भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) को आगे बढ़ाते हुए 3.5 करोड़ पाउंड के मिसाइल आपूर्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता केवल आर्थिक सहयोग का नहीं, बल्कि सामरिक साझेदारी का भी एक स्पष्ट संदेश है। हम आपको बता दें कि भारत और ब्रिटेन के बीच 3.5 करोड़ पाउंड (लगभग 468 मिलियन डॉलर) का जो मिसाइल आपूर्ति अनुबंध हुआ है उसके तहत यूके निर्मित हल्की बहुउद्देशीय मिसाइलों की आपूर्ति की जाएगी। थेल्स यूके द्वारा निर्मित हल्की बहुउद्देशीय मिसाइलें भारतीय सेना की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगी, जैसे कि विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को निशाना बनाना। इससे भारतीय सेना की सामरिक क्षमताओं में वृद्धि होगी और विभिन्न युद्ध परिस्थितियों में उनकी प्रभावशीलता में सुधार होगा।

हम आपको यह भी याद दिला दें कि तीन वर्षों की लंबी बातचीत के बाद जुलाई 2025 में अंतिम रूप दिए गए CETA ने दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार का मार्ग प्रशस्त किया। इसका उद्देश्य न केवल वस्तुओं और सेवाओं के आयात-निर्यात को सुगम बनाना है, बल्कि छोटे और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को सशक्त करना और युवाओं के लिए रोजगार सृजन को बढ़ावा देना भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि यह समझौता 2030 तक भारत-यूके व्यापार को वर्तमान 56 अरब डॉलर से दोगुना करने में सहायक होगा।

सिर्फ व्यापार ही नहीं, शिक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी समझौतों का महत्व है। नौ प्रमुख ब्रिटिश विश्वविद्यालय अब भारत में अपने कैंपस खोल रहे हैं, जिससे शिक्षा का आदान-प्रदान बढ़ेगा और भारत में उच्च शिक्षा के स्तर को अंतरराष्ट्रीय मानक पर लाया जा सकेगा। ब्रिटिश फिल्म संस्थान और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के बीच समझौते से फिल्म निर्माण और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा। ये सभी कदम भारत-यूके रिश्तों को केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी मजबूत करते हैं। इसके अलावा, 3.5 करोड़ पाउंड के मिसाइल आपूर्ति अनुबंध से स्पष्ट है कि दोनों देश केवल व्यापारिक साझेदार नहीं हैं, बल्कि सामरिक साझेदारी में भी गहराई ला रहे हैं। यह समझौता भारत की सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के साथ-साथ ब्रिटेन को भारतीय रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक foothold प्रदान करता है। वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, जहां भारत-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और चीन जैसी बढ़ती महाशक्ति का संतुलन महत्वपूर्ण है, ब्रिटेन के लिए भारत एक भरोसेमंद साझेदार बन गया है। प्रधानमंत्री स्टारमर ने भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सदस्यता के समर्थन की भी पुष्टि की, जो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका को मान्यता देने के समान है। यह दोनों देशों के साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और वैश्विक स्थिरता में योगदान को भी रेखांकित करता है।

ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो यह स्थिति अत्यंत दिलचस्प है। एक समय ब्रिटेन भारत पर राज करता था, उसकी संपत्तियों और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता था। लेकिन अब वही ब्रिटेन आर्थिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत के दरवाजे पर खड़ा है। इसकी प्रमुख वजह भारत का वैश्विक आर्थिक प्रभाव, उभरती मध्यवर्गीय शक्ति, तकनीकी दक्षता और वैश्विक व्यापार में बढ़ता योगदान है। ब्रिटेन की यूरोप और अमेरिका पर निर्भरता कम हुई है और अब उसे भारत की मार्केट, प्रतिभा और सामरिक शक्ति की सख्त आवश्यकता है।

इस बदलाव के कई कारण हैं। पहला, वैश्विक आर्थिक केंद्रों का पूर्व से दक्षिण-पूर्व की ओर शिफ्ट होना। दूसरा, ब्रिटेन की आर्थिक चुनौतियाँ— ब्रेक्सिट के बाद व्यापारिक और निवेश संबंधों में अस्थिरता। तीसरा, रक्षा और तकनीकी सहयोग के लिए नए, विश्वसनीय साझेदार की आवश्यकता। भारत इस परिप्रेक्ष्य में ब्रिटेन के लिए सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक रणनीतिक साझेदार बन गया है।

देखा जाये तो आज की वैश्विक राजनीति अस्थिर है। चीन का उदय, रूस-यूक्रेन संघर्ष, मध्य-पूर्व की जटिलताएँ और अमेरिका-यूरोप के आंतरिक दबाव। ऐसे समय में भारत-यूके साझेदारी एक स्थिर और भरोसेमंद विकल्प प्रस्तुत करती है। दोनों देश न केवल व्यापार और रक्षा में सहयोग करेंगे, बल्कि वैश्विक मंचों पर सुरक्षा, लोकतंत्र और आर्थिक विकास के साझा एजेंडे को भी आगे बढ़ाएंगे।

विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में मिसाइल और तकनीकी सहयोग, शिक्षा क्षेत्र में ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के कैंपस और सांस्कृतिक साझेदारी जैसे पहलुओं से स्पष्ट है कि यह साझेदारी केवल आर्थिक हितों तक सीमित नहीं है। यह दोनों देशों के लिए लंबी अवधि की रणनीति का हिस्सा है, जो उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत स्थिति प्रदान करेगा।

देखा जाये तो भारत और ब्रिटेन के रिश्ते अब इतिहास और आधुनिकता का मिश्रण हैं। एक समय ब्रिटेन भारत पर शासन किया करता था, आज वही भारत से सहयोग माँग रहा है। यह बदलाव केवल आर्थिक या सामरिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी गहरा है। CETA, मिसाइल अनुबंध और शिक्षा-सांस्कृतिक समझौते इस बदलती वास्तविकता के प्रतीक हैं। सामरिक रूप से देखें तो भारत की तकनीकी और रक्षा क्षमता ब्रिटेन के लिए एक अनिवार्य संसाधन बन चुकी है। आर्थिक रूप से भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते दोनों देशों के लिए लाभकारी होंगे। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में यह साझेदारी लोकतंत्र, स्थिरता और वैश्विक व्यापार के साझा मूल्यों को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम है।

अभियान

जय-विजय का पतन और भगवान के अवतार का रहस्य

भगवान शंकर एक बार कैलाश पर माता पार्वती को भगवान विष्णु के अद्भुत चरित्र का वर्णन कर रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि माता पार्वती किसी रहस्य से वंचित रह जाएँ। इस संदर्भ में उन्होंने जय और विजय की कथा सुनाई, जो भक्ति, अहंकार और मोक्ष का गहरा संदेश देती है।

जय और विजय, जो स्वयं भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, अहंकार में इतने अंधे हो गए कि साधु-संतों की महिमा भी उन्हें दिखाई नहीं दी। वे नहीं समझ सके कि जिन मुनियों को वे रोक रहे थे, वे कोई सामान्य योगी नहीं, बल्कि ब्रह्मस्वरूप संत हैं। संतों का अपमान करना, स्वयं भगवान के द्वार को ठुकराने के समान है।

संतों ने देखा कि द्वारपाल अहंकार में डूबे हुए हैं, तब उन्होंने कहा —

"हे दुष्टों! तुम्हारा स्वभाव

राक्षसों के समान है। भगवान ने तुम्हें द्वार पर रखा, पर तुमने मर्यादा भूल दी। अब तीन जन्मों तक तुम्हें राक्षस योनि में जाना होगा।"

जय और विजय का गर्व इस शाप को सुनते ही भस्म हो गया। उन्होंने मुनियों से क्षमा मांगी। साधुकरुणामय थे — उन्होंने कहा कि हर जन्म में भगवान स्वयं अवतरित होकर उनका उद्धार करेंगे। इस प्रकार शाप ही वरदान बन गया।

पहले जन्म में जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। भगवान विष्णु ने वराह और नरसिंह अवतार लेकर उनका विनाश किया।

दूसरे जन्म में वे रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे। रावण ने माता सीता का अपहरण किया, पर भगवान ने राम रूप में अवतार लेकर उनका संहार किया।

तीसरे जन्म में वही आत्माएँ शिशुपाल और दंतवक्र बनीं, जिनका उद्धार भगवान श्रीकृष्ण ने किया। इस प्रकार भगवान ने अपने प्रिय द्वारपालों को तीन बार जन्म देकर मुक्ति प्रदान की।

भगवान शंकर ने पार्वती को बताया कि सत्य मुक्ति का मार्ग संतों और गुरु की शरण से होकर जाता है। अहंकार ही पतन का मूल कारण है। साधु-संतों का अपमान जीवन का सबसे बड़ा पाप है। बैकुण्ठ का द्वार विनम्रता के बिना भी नरक बन सकता है, और साधु-संग नरक में भी बैकुण्ठ का आनंद दे सकता है। शंकर ने समझाया —

"प्रभु के प्रत्येक अवतार का उद्देश्य धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश और भक्तों की रक्षा है। जय और विजय की कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान की करुणा अनंत है। उन्होंने अपने द्वारपालों को तीन जन्म देकर मोक्ष प्रदान किया।"

पार्वती जी भाव-विभोर होकर सुनती रहीं। उन्होंने विनम्र स्वर में पूछा कि भगवान के अन्य अवतारों के पीछे कौन से रहस्य छिपे हैं। शंकर मुस्कराए और बोले —

"प्रत्येक अवतार धर्म की रक्षा और भक्तों के उद्धार के लिए होता है। अगली कथा में मैं यह रहस्य विस्तार से बताऊँगा।"

इतना कहकर भोलेनाथ समाधि में लीन हो गए। पार्वती जी ने उनके चरणों में शीश झुकाया और श्रीहरि का नाम जपने लगीं। उस क्षण कैलाश पर्वत भक्ति और दिव्य आभा से आलोकित हो गया, और दिशाओं में "जय श्रीराम" और "हरि बोल" की पवित्र ध्वनि गूँज उठी।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

माननीय रेलवे, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद मण्डल का दौरा किया

(जीएनएस)। गुजरात में लॉजिस्टिक्स अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को सशक्त बनाने हेतु दो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए

वडनगर स्टेशन, हाई स्पीड रेलवे (HSR) साबरमती स्टेशन और डिपो का किया निरीक्षण

माननीय रेलवे, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज 09 अक्टूबर, 2025 को पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल का दौरा किया। महेसाणा में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट में भाग लिया।

माननीय रेल मंत्री जी ने वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट के दौरान अपने भाषण में कहा कि रेलवे हमारे देश की लाइफलाइन है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने और ग्रीन लॉजिस्टिक्स का सबसे बड़ा माध्यम है। बहुत खुशी होती है जब रेलवे के नए-नए प्रोजेक्ट्स देशभर में शुरू होते हैं। गुजरात में फ्रेट कॉरिडोर का काम पूरा हो गया है और उसका बहुत लाभ देश को मिल रहा है। जहाँ किसी कंटेनर ट्रेन को

आने में 30-30 घंटे लगते थे, आज वहाँ 10-11 घंटे में कंटेनर ट्रेन पहुँच जाती है। आज फ्रेट कॉरिडोर पर डेली करीब-करीब 400 गाड़ियाँ चल रही हैं तथा पिछले 11 वर्षों में गुजरात में 2,764 किमी रेलवे ट्रैक बने हैं। जो डेनमार्क के कुल रेल नेटवर्क के बराबर ट्रैक गुजरात में 11 वर्षों में बने। गुजरात में रेलवे का इन्वेस्टमेंट 1 लाख 46 हजार करोड़ है।

वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट के दौरान गुजरात में मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कुल 12,877.35 करोड़ के दो महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए।

पहला समझौता भारतीय रेल (पश्चिम रेलवे, अहमदाबाद मण्डल) और उद्योग आयुक्तालय, गुजरात सरकार के बीच हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में लॉजिस्टिक्स अवसंरचना और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना है। इस समझौते के तहत रेलवे और गैर-रेलवे भूमि पर गति शक्ति मल्टीकार्गो टर्मिनल, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और एकीकृत लॉजिस्टिक्स एवं औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। ये परियोजनाएँ गुजरात इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स मास्टर प्लान और सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान्स के अनुरूप होंगी। इसके अलावा, माल परिवहन से संबंधित डेटा का नियमित आदान-प्रदान गुजरात लॉजिस्टिक्स डैशबोर्ड के माध्यम से किया जाएगा, जिससे राज्य में लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक निर्णय और भी सटीक और प्रभावी बन सकेंगे।

दूसरा समझौता भारतीय रेल और गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (GSRTC) के बीच हुआ। इसके तहत राज्य के प्रमुख 87 रेलवे स्टेशनों को मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इन हब्स में रेल और बस सेवाओं का एकीकृत संचालन होगा, जिससे यात्रियों को निर्बाध, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित होगी। इन हब्स में आधुनिक सुविधाएँ, लॉजिस्टिक्स समन्वय केंद्र और यात्री सेवाओं का समेकन होगा, जिससे राज्य में आवागमन और माल परिवहन दोनों में तेजी और दक्षता आएगी।

अपने दौरे के दौरान श्री वैष्णव ने वडनगर स्टेशन का भी निरीक्षण किया, जहाँ उन्होंने यात्री सुविधाओं का बारीकी से अवलोकन किया तथा इस स्टेशन के पुनर्विकास के बारे में चर्चा की। साथ ही स्थानीय लोगों से बातचीत की तथा उनकी ट्रेनों की मांग पर भी विचार-विमर्श किया।

माननीय रेल मंत्री श्री जी ने साबरमती रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का निरीक्षण किया एवं स्टेशन के मॉडल का अवलोकन किया तथा साबरमती हाई स्पीड रेल स्टेशन एवं हाई स्पीड रेल डिपो का विस्तृत निरीक्षण किया और मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्हें NHSRCL के अधिकारियों द्वारा प्रजेंटेशन के माध्यम से परियोजना में किए गए विभिन्न विकासात्मक कार्यों और नवीनतम प्रगति की जानकारी दी गई।

निरीक्षण के दौरान माननीय रेल मंत्री जी के साथ श्री विवेक कुमार गुप्ता, महाप्रबंधक, पश्चिम रेलवे; श्री वेद प्रकाश, मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद; प्रमुखाध्यक्ष पश्चिम रेलवे मुख्यालय एवं अहमदाबाद मंडल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मध्य रेल सोलापुर मंडल ने स्वच्छता पखवाड़े में दिखाई मिसाल

(जीएनएस)। सोलापुर। मध्य रेल के सोलापुर मंडल ने स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के तहत दो दिवसीय विशेष अभियान चलाकर रेलवे परिसर और पटरियों को स्वच्छ बनाए रखने में उत्कृष्ट पहल की। 7 और 8 अक्टूबर को मंडल ने क्रमशः "स्वच्छ पटरी" और "स्वच्छ परिसर" पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक सफाई अभियान आयोजित किया। यह पहल न केवल रेल कर्मचारियों बल्कि यात्रियों के लिए भी सुरक्षित और स्वच्छ परिवेश सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई। 7 अक्टूबर को आयोजित "स्वच्छ पटरी" अभियान में रेलवे पटरियों और आसपास के क्षेत्रों में बिखरी अवांछित वनस्पति, झाड़ियाँ, घास और कचरा हटाने पर जोर दिया गया। प्रमुख क्षेत्रों में बबलाद-कलबुरगि-हिरेनंदुरु खंड, कलबुरगि यार्ड, पंढरपुर खंड और सोलापुर स्टेशन यार्ड शामिल थे। सफाई टीमों ने पटरियों के किनारे गहन निरीक्षण कर अवांछित सामग्री हटाई और ट्रेनों के परिचालन क्षेत्र को सुरक्षित बनाया।

8 अक्टूबर को "स्वच्छ परिसर" के

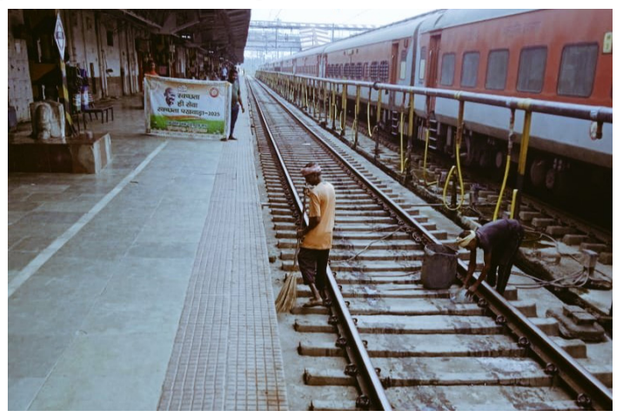

अंतर्गत रेलवे कॉलोनियों, विश्राम कक्षों, प्रतीक्षालय, विश्राम गृह और छात्रावास की सफाई की गई। सोलापुर की रेलवे कॉलोनियाँ, एसी वेटिंग हॉल, कलबुरगि व पंढरपुर के कॉलोनी एवं रनिंग रूम, लातूर वाडी और कुर्डुवाडी की कॉलोनियों को विशेष ध्यान दिया गया। कर्मचारियों ने परिसर के हर कोने की सफाई सुनिश्चित करते हुए कार्यस्थलों और आवासीय क्षेत्रों को साफ-सुथरा बनाया।

मंडल प्रबंधन ने बताया कि इन निरंतर प्रयासों के माध्यम से सोलापुर मंडल ने "स्वच्छ रेल - स्वच्छ भारत" मिशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। इस पहल ने सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी को प्रेरित किया और रेलवे परिसर को स्वच्छ, सुरक्षित और हरित बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) – उत्तर गुजरात

गुजरात ग्रीन ग्रोथ के लिए प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- गुजरात आज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में देश का नेतृत्व करने को तैयार
- देश में सौर ऊर्जा की नींव उत्तर गुजरात में रखी गई थी
- गुजरात ने सौर ऊर्जा के साथ ही पवन ऊर्जा क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है

केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी :-

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ऊर्जा क्रांति आ रही है
- देश में उत्पन्न होने वाली कुल नवीकरणीय ऊर्जा में से एक तिहाई ऊर्जा अकेले गुजरात उत्पन्न करता है

सेमिनार में राज्य के ऊर्जा मंत्री श्री कनुभाई देसाई और कैबिनेट मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल की प्रोत्साहक उपस्थिति

समारोह में ऊर्जा क्षेत्र के 22 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए

(जीएनएस)। गांधीनगर, : वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत गुरुवार को मेहसाणा में ऊर्जा आत्मनिर्भरता पर आयोजित सेमिनार और अवॉर्ड समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि 2003 में जब वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत हुई थी, तब 100-200 करोड़ रुपए के एमओयू हुए थे, जबकि आज पचास हजार करोड़ रुपए जैसी बड़ी धनराशि के एमओयू हो रहे हैं, जो गुजरात की अर्थव्यवस्था में आए बड़े परिवर्तन का दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान गुजरात में पंचामृत यानी जल शक्ति, ज्ञान शक्ति, ऊर्जा शक्ति, जन शक्ति और रक्षा शक्ति पर आधारित शासन का नया मॉडल विकसित किया था। आज गुजरात देश का ग्रीन एनर्जी हब बनने जा रहा है। गुजरात आज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में देश का नेतृत्व करने को तैयार है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि दुनिया जब ऊर्जा का विकल्प तलाश रही थी, तब प्रधानमंत्री ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सौर ऊर्जा पर जोर देकर उत्तर गुजरात के चारणका में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थापित किया था। देश में सौर ऊर्जा की नींव उत्तर गुजरात की भूमि में रखी गई थी। ऐसे प्रयासों के कारण ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा श्री मोदी को नीतिगत नेतृत्व के लिए 'चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2018' पुरस्कार से नवाजा गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात ने नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए विशेष नीति बनाई है। वाइब्रेंट समिट में ग्रीन हाइड्रोजन नीति की घोषणा की गई थी। उन्होंने कहा कि गुजरात ग्रीन ग्रोथ के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बनाई गई पीएम सूर्य घर जैसी योजना के कार्यान्वयन में गुजरात अग्रणी रहा है। पूरे गुजरात में तीन लाख से अधिक सौलर रूफटॉप पैनल्स लगाए गए हैं। जिसमें मोढेरा और बनासकांठा के मशाली जैसे सौ फीसदी सोलर संचालित गांव उत्तर गुजरात में स्थित हैं। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के साथ-साथ गुजरात ने पवन ऊर्जा (विंड एनर्जी) के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कच्छ के खावड़ा में कार्यरत हो रहा है। 2001 में नवीकरणीय ऊर्जा से केवल 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, जो आज बढ़कर 31,403 मेगावाट तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पर

बल देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ 'आत्मनिर्भर भारत' का मंत्र दिया है। आगामी वर्षों में भारत की ऊर्जा जरूरत में वृद्धि होगी, तब नवीकरणीय ऊर्जा से बिजली हासिल कर इस ऊर्जा खपत की आवश्यकता को पूरा किया जा सकेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने यह दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गुजरात ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने को तैयार है।

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी

सेमिनार में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ऊर्जा क्षेत्र में जो परिवर्तन आए हैं, उससे देश में ऊर्जा क्रांति आ रही है। आज वाइब्रेंट गुजरात में ऊर्जा क्षेत्र में हुए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) को देखकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि एक समय था जब देश में अंधकार छाया रहता था, जबकि आज देश में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि गुजरात देश भर में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। पीएम कुसुम और पीएम सूर्य घर जैसी रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र की योजनाओं के क्रियान्वयन के मामले में भी गुजरात सबसे आगे है। देश में उत्पन्न होने वाली कुल नवीकरणीय ऊर्जा में से एक तिहाई ऊर्जा-बिजली अकेला गुजरात उत्पन्न करता है।

देश ही नहीं, संभवतः दुनिया के पहले सोलर विलेज मोढेरा का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जब इस विश्वास के साथ सूर्य घर योजना की बात की थी कि हर घर बिजली पैदा करेगा, तब लोग इस बात का मजाक उड़ाते थे, लेकिन दूरदर्शी नेता वही होता है, जो अगले 20-25 वर्षों का भविष्य देख सकता है।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हुआ है। भारत ने वर्ष 2030 तक 100 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य रखा है, जो समय से पहले ही हासिल हो सकता है। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा अनिवार्य है।

राज्य के ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एस.जे. हैदर ने स्वागत भाषण में कहा कि वाइब्रेंट गुजरात का यह कार्यक्रम ऊर्जा, उद्यम और उन्नति की यात्रा है। यह गुजरात का ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ता कदम है। गुजरात की ऊर्जा यात्रा में नए ऊर्जा स्रोत हमारे भविष्य को और अधिक आसान और ऊर्जावान बनाएंगे।

इस सेमिनार में टोरेन्ट कंपनी के प्रबंधन निदेशक श्री जिनल मेहता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नवीकरणीय ऊर्जा का विजन दिया है। भारत सरकार ने इस विजन के अनुरूप विभिन्न योजनाएं लॉन्च की हैं, जिनमें गुजरात एक अग्रणी राज्य है।

आईआईटी-गांधीनगर के निदेशक प्रो. रजत मूना ने वर्ष 2030 तक 100 गीगावाट ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए गुजरात सरकार को बधाई दी।

अवाडा समूह के चेयरमैन श्री विनीत मित्तल और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक श्री गुरदीप सिंह ने 'ग्रीन एनर्जी के अंतर्गत उद्यमिता और निवेशक' विषय पर विस्तार से रोशनी डाली।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री और महानुभावों ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की नीति से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों के संकलन वाली पुस्तकों का विमोचन किया। ऊर्जा आत्मनिर्भरता के गुजरात के प्रयासों की गाथा दर्शाने वाली फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया।

इस मौके पर ऊर्जा क्षेत्र के 22 एमओयू का आदान-प्रदान किया गया। ऊर्जा क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले तथा क्लीन-ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले श्री गणपतभाई पटेल सहित अन्य लोगों तथा संस्थानों और कंपनियों को सम्मानित कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। सेमिनार में राज्य के ऊर्जा मंत्री श्री कनुभाई देसाई, कैबिनेट मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल, मुख्य सचिव श्री पंकज जोशी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री एम.के. दास, स्थानीय सांसद और विधायकगण, ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों के अग्रणी और उद्योगपतियों सहित बड़ी संख्या में प्रतिनिधि मौजूद रहे।

प्रथम वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस – उत्तर गुजरात मेहसाणा

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के साथ इसरो के अध्यक्ष डॉ. वी. नारायणन की मुलाकात बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में पिछले 11 वर्षों में भारत ने 90 से अधिक उपक्रमों की सफलता प्राप्त की है

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के साथ इसरो के अध्यक्ष डॉ. वी. नारायणन ने वन टु वन बैठक आयोजित कर इसरो तथा अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्र की विभिन्न उपलब्धियों की चर्चा की। डॉ. नारायणन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा तथा निरंतर मार्गदर्शन से इसरो ने पिछले 11 वर्षों में 90 से अधिक उपग्रहों की सफलता प्राप्त की है। इतना ही नहीं, भारत अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में विकसित राष्ट्र की पंक्ति में खड़ा है।

मुख्यमंत्री ने इसरो की इस उपलब्धि के लिए डॉ. नारायणन को अभिनंदन दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा स्पेस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को भी अवसर दिए जाने की प्रशंसा की।

गुजरात में इसरो को आवश्यक भूमि के प्रस्ताव के विषय में भी मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार का पॉजिटिव अप्रोच दर्शाया। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री पंकज जोशी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, उद्योग विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती ममता वर्मा, मुख्यमंत्री की अपर प्रधान सचिव श्रीमती अवंतिका सिंह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव श्रीमती पी. भारती भी उपस्थित रहे।

विश्व बैंक के दक्षिण एशिया के उपाध्यक्ष श्री जोहान्स जुट ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के साथ की वन टू वन बैठक

गुजरात के व्यापारियों और उद्यमियों को ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़ने के लिए विश्व बैंक की उत्सुकता दिखाई

(जीएनएस)। गांधीनगर : उत्तर गुजरात क्षेत्र के लिए दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) मेहसाणा के खेरवा गांव में आयोजित हो रही है।

वीजीआरसी के पहले दिन गुरुवार को वन टू वन बैठकों का दौर चला, जिसमें दक्षिण एशिया के लिए विश्व बैंक के उपाध्यक्ष श्री जोहान्स जुट के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के साथ बैठक की।

उन्होंने गुजरात के व्यापारियों और उद्यमियों को ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़ने के लिए विश्व बैंक की उत्सुकता दर्शायी। उन्होंने गुजरातियों के व्यापार कौशल और बाजार-व्यवसाय क्षमताओं की सराहना भी की।

मुख्यमंत्री के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि कार्बन क्रेडिट लिंक फाइनेंस प्रोडक्ट के जरिए सस्टेनेबल फाइनेंसिंग की नई दिशा खुल सकती है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने वीजीआरसी की प्रदर्शनी में विश्व बैंक द्वारा लगाए गए स्टॉल में कृषि क्षेत्र के

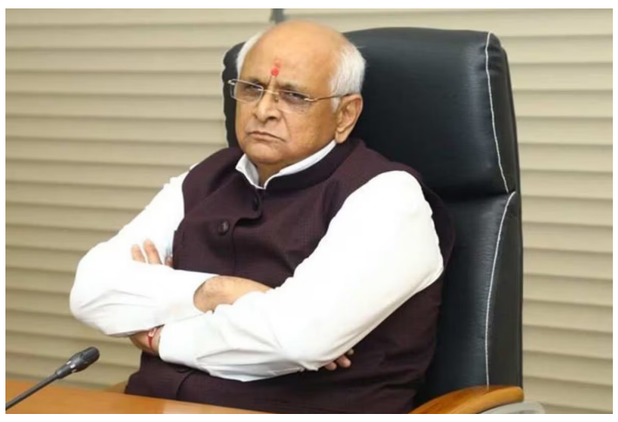

लिए फाइनेंस किए गए राज्यों और राष्ट्रों की सर्वोत्तम प्रथाओं को दिखाने के लिए उनकी सराहना की।

उन्होंने ऐसी सर्वोत्तम प्रथाओं को गुजरात के साथ साझा करने का अनुरोध भी किया। श्री पटेल ने इस बात पर भी चर्चा की कि एडटेक (शिक्षा प्रौद्योगिकी) जैसे उभरते क्षेत्रों में निहित विकास की संभावनाओं को किस प्रकार विश्व बैंक के सहयोग से गुजरात में उपयोग में लिया जा सकता है। इस वन टू वन बैठक में मुख्य सचिव श्री पंकज जोशी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री एम.के. दास, कृषि एवं सहकारिता विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती अंजू शर्मा, ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एस.जे. हैदर, उद्योग विभाग की प्रधान सचिव सुश्री ममता वर्मा, मुख्यमंत्री की अपर प्रधान सचिव श्रीमती अवंतिका सिंह और सचिव डॉ. विक्रांत पांडे भी मौजूद रहे।

केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने गुजरात के पहले ग्रीन रेलवे स्टेशन – एकता नगर का किया दौरा

(जीएनएस)। केंद्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने दिनांक 09 अक्टूबर 2025 को भारत के सबसे सुंदर और आधुनिक रेलवे स्टेशनों में से एक तथा गुजरात के पहले "ग्रीन रेलवे स्टेशन" एकता नगर का दौरा किया।

श्री सोमन्ना ने रेलवे स्टेशन परिसर का निरीक्षण कर स्वच्छता, आधुनिक सुविधाओं एवं ग्रीन टेक्नोलॉजी से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

मीडिया को संबोधित करते हुए श्री सोमन्ना ने बताया कि पिछले 11 वर्षों में भारतीय रेल ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को साकार करते हुए उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2025-26 में गुजरात को 17,155 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है, जो वर्ष 2009 -14 के आवंटन के मुकाबले 29 गुना है। वर्ष 2014 से अभी तक गुजरात में 2739 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक का निर्माण किया गया तथा 3,144 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को विद्युतीकृत किया गया है। गुजरात राज्य में 87 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशनों के रूप में विकसित किया जा रहा है। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करते हुए गुजरात में विभिन्न स्टेशनों पर 97 लिफ्टों और 50 एस्कलेटरों का निर्माण किया गया है, साथ ही 335 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस समय गुजरात राज्य में चार वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन हो रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एकता नगर, वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत और राजकोट जैसे शहरों में रेलवे सुविधाओं को आधुनिक स्तर तक पहुँचाया गया है। प्रधानमंत्री के "विकसित भारत 2047" के विज़न में रेलवे की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

एकता नगर स्टेशन पर निरीक्षण से पहले माननीय रेल राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना जी ने आज वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके के साथ सूरत-एकता नगर खंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान, उन्होंने रेल पटरियों की सुरक्षा और परिचालन दक्षता की समीक्षा की। उन्होंने मंडल के ट्रैक सेफ्टी एवं परिचालन दक्षता के साथ चल रही विकास परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई।

माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने साबरमती हाई स्पीड रेल (HSR) स्टेशन का निरीक्षण किया

(जीएनएस)। माननीय रेलवे, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज 09.10.2025 को अहमदाबाद में स्थित साबरमती हाई स्पीड रेल (HSR) स्टेशन का निरीक्षण किया। यह स्टेशन देश के पहले मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर (बुलेट ट्रेन परियोजना) का एक महत्वपूर्ण टर्मिनल है जिसका निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है।

साबरमती हाई स्पीड स्टेशन को एक विश्व-स्तरीय मल्टी-मॉडल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहाँ भारतीय रेल, हाई स्पीड रेल (HSR), मेट्रो रेल तथा बस रैपिड ट्रांजिट रूट (BRT) का सहज एकीकरण सुनिश्चित किया गया है। इस बहु-मॉडल कनेक्टिविटी से यात्रियों को एक ही परिसर में विभिन्न परिवहन माध्यमों के बीच आसान और त्वरित परिवहन सुविधा प्राप्त होगी।

इस स्टेशन में A बिल्डिंग में 9 फ्लोर एवं B बिल्डिंग 8 हैं,तथा 1400 से अधिक वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था है।

जिनमें अत्याधुनिक यात्री सुविधाएँ जैसे वेटिंग लाउंज, टिकटिंग जोन, कॉनकोर्स एरिया, प्लेटफॉर्म, एस्केलेटर, एलिवेटर, डिजिटल सूचना प्रणाली और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, रूफ प्लाज़ा, प्लेटफॉर्म क्षेत्र तथा लैंडस्केपिंग का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। स्टेशन परिसर को पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा-कुशल बनाने के लिए ग्रीन बिल्डिंग मानकों के अनुरूप डिजाइन किया गया है।

इस अवसर पर नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) के अधिकारियों ने एक विस्तृत प्रेजेंटेशन के माध्यम से परियोजना की वर्तमान स्थिति, नवीनतम तकनीकी नवाचारों, निर्माण प्रगति एवं भविष्य की कार्ययोजना की जानकारी दी।

साबरमती HSR स्टेशन के शुरू होने से गुजरात और महाराष्ट्र के बीच संपर्क में महत्वपूर्ण सुधार होगा तथा क्षेत्रीय आर्थिक विकास, औद्योगिक गतिविधियों और पर्यटन को भी नई गति मिलेगी।

पश्चिम रेलवे

रेल एवं स्लीपर नवीनीकरण कार्य

मंडल रेल प्रबंधक (WA), पश्चिम रेलवे, मुंबई सेंट्रल,मुंबई 400 008. ई-निविदा सूचना क्रमांक: BCT/25-26/244 दिनांक 06.10.2025 आमंत्रित करता है। कार्य एवं स्थान: उकाई सोनगढ़ - जलगांव खंड:- रेल नवीनीकरण के माध्यम से (P) - 5.131 Tkm और रेल नवीनीकरण के माध्यम से (P) - 7.69 Tkm ठेकेदार के PQRS पोर्टल द्वारा। कार्य की अनुमानित लागत: रु. 2,08,30,122.61 EMD: रु. 2,54,200/-। जमा करने की तिथि एवं समय: दिनांक 31.10.2025 को 15:00 बजे तक। खुलने की तिथि एवं समय: दिनांक 31.10.2025 को 15:30 बजे। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएँ। मैन्युअल प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

0689

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

गरबा पर पथराव भारी पड़ा: गांधीनगर में 186 अवैध इमारतों पर बुलडोजर कार्रवाई

(जीएनएस)। गांधीनगर। गुजरात के बहियाल गांव में 24 सितंबर को नवरात्रि के दौरान हुई हिंसा और पथराव ने प्रशासन को कड़ी कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया। भूपेंद्र पटेल सरकार ने इस मामले में तत्काल प्रभाव से कदम उठाया और गुरुवार, 9 अक्तूबर की सुबह से अवैध कब्जों को ध्वस्त करने का अभियान शुरू किया। पहले चरण में 186 अवैध इमारतों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बुलडोजर द्वारा जमींदोज किया गया। इस कार्रवाई में इलाके में 500 से अधिक पुलिस कर्मी, 20 जेसीबी मशीनें और 50 ट्रक तैनात किए गए, ताकि अतिक्रमण तेजी से हटाया जा सके और सुरक्षा सुनिश्चित हो।

घटना 24 सितंबर की रात हुई थी, जब बहियाल गांव में अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोग सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद में फंस गए। इस झड़प में लगभग 200 लोग शामिल थे, और कई दुकानों व वाहनों को नुकसान पहुंचा, जबकि कुछ को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने इस दंगे में शामिल करीब 60 लोगों को हिरासत में लिया था।

गांधीनगर पुलिस अधीक्षक रवि तेजा वासमसेट्टी ने बताया कि कार्रवाई में ध्वस्त किए जा रहे प्रतिष्ठानों में लगभग 50 हिस्ट्रीशीटर भी शामिल हैं। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया कि यह अभियान उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और पंचायत अधिकारियों की मौजूदगी में किया जाए और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया तेज और प्रभावी ढंग से पूरी की जाए।

यह कड़ा कदम इस बात का संकेत है कि सरकार अवैध कब्जों और हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगी। नवरात्रि जैसे सांस्कृतिक आयोजनों के दौरान शांति और कानून--व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अवैध अतिक्रमण और हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में कोई भी समूह किसी भी बहाने से सामाजिक व्यवस्था को बाधित न कर सके।

नासिक कुंभ मेले को लेकर राजनीति गर्म, कांग्रेस ने महायुति सरकार पर साधा निशाना

(जीएनएस)। मुंबई। महाराष्ट्र में नासिक कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। कांग्रेस ने सत्तारूढ़ महायुति सरकार पर आरोप लगाया है कि धार्मिक आयोजन के नाम पर हजारों करोड़ रुपये के बजट की "मलाई लूटने" की होड़ मची हुई है, जबकि किसानों और आम जनता की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि सरकार धार्मिक आयोजनों के बहाने भ्रष्टाचार और फिजूलखर्ची में जुटी हुई है, जबकि राज्य के कई हिस्सों में हुई अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण किसानों की खरीफ फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। सपकाल ने केंद्र और राज्य सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग की, जिसमें प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये की सहायता और जिन किसानों की जमीन बह गई है, उनके लिए प्रति हेक्टेयर 5 लाख रुपये की भरपाई शामिल हो। उन्होंने आरोप लगाया कि कुंभ मेला के बहाने ठेकेदारों, नेताओं और नौकरशाहों का गठजोड़ सक्रिय हो गया है, और फंड वितरण में पारदर्शिता नहीं दिखाई दे रही।

कांग्रेस ने कानून-व्यवस्था पर भी सरकार पर हमला बोला। सपकाल ने कहा कि नासिक जैसे पवित्र शहर में नशे का व्यापार खुलेआम चल रहा है, और ड्रग्स माफिया पर कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने बताया कि पिछले 9 महीनों में शहर में 44 हत्याएं हुई हैं और राज्य में पूर्णकालिक गृह मंत्री न होने के कारण कानून-व्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने नासिक के ड्रग नेटवर्क का 'गुजरात कनेक्शन' उजागर करने की भी मांग की।

सपकाल ने विवादित गृह राज्यमंत्री योगेश कदम पर भी निशाना साधा और उनके खिलाफ बर्खास्तगी की मांग की। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई पर हुए हमले को अत्यंत निंदनीय बताते हुए कहा कि यह केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि न्यायपालिका और संविधान की प्रतिष्ठा पर प्रहार है।

कांग्रेस ने कहा कि राज्य की राजनीति अब विकास और जनहित से हटकर केवल ठेकों, कमीशनों और सत्ता की साझेदारी तक सीमित हो गई है। नासिक कुंभ मेला, जो देशभर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, अब सत्तारूढ़ दलों की खींचतान का नया अखाड़ा बन गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह हमला कुंभ मेले के बहाने नहीं, बल्कि 2026 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले सरकार विरोधी माहौल बनाने की रणनीति का हिस्सा है, और आने वाले महीनों में फंड बंटवारे और तैयारियों को लेकर और आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिल सकते हैं।

प्रधानमंत्री 11 अक्टूबर को शुरू करेंगे 'प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना' और 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन'

(जीएनएस)। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर 2025 को पूसा, दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री कृषि अवसंरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं का भी उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे।

दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत देश में दालों के उत्पादन को बढ़ाने, उच्च उत्पादकता वाले और कीट-प्रतिरोधी बीज किसानों तक समय पर पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज और 88 लाख निःशुल्क बीज किट वितरित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य किसानों को उन्नत बीज और कृषि तकनीक तक पहुँच प्रदान कर उत्पादन में सुधार करना है।

प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना का उद्देश्य कम उत्पादकता वाले जिलों में फसल की उत्पादकता बढ़ाना है। इसके लिए योजना में सिंचाई, भंडारण, ऋण सुविधाएं और फसल विविधिकरण जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। योजना की निगरानी नीति आयोग करेगा ताकि सभी उपाय प्रभावी रूप से लागू हों और किसानों को वास्तविक लाभ मिल सके। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसानों, एफपीओ, सहकारी समितियों और तकनीकी नवाचारों में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित करेंगे। देशभर के लगभग 1 करोड़ किसान इस कार्यक्रम से सीधे या ऑनलाइन जुड़ेंगे और उन्हें योजनाओं से मिलने वाले लाभों की जानकारी दी जाएगी। यह पहल भारतीय कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने, आत्मनिर्भरता और किसानों की आय सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

असम में भाजपा को झटका, पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेन गोहेन समेत 18 नेताओं का इस्तीफा

(जीएनएस)। डिब्रूगढ़। असम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और चार बार के सांसद राजेन गोहेन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ कुल 17 अन्य नेताओं ने भी भाजपा से त्यागपत्र सौंपा। राजेन गोहेन ने यह निर्णय राज्य भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया को लिखे पत्र के जरिए बताया और कहा कि वे पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी जिम्मेदारियों से तुरंत प्रभाव से हट रहे हैं। राजेन गोहेन ने इस्तीफे का कारण बताते हुए कहा कि भाजपा ने असम के लोगों से किए गए वादों को पूरा नहीं किया और स्थानीय समुदायों के हितों की अनदेखी करते हुए बाहरी लोगों को राज्य में बसने की अनुमति दी। उनके अनुसार यह स्थिति उन्हें असंतुष्ट और निराश कर गई।

राजेन गोहेन ने 1999 से 2019 तक नागांव संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और 2016 से 2019 तक रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री भी रहे। भाजपा में रहते हुए उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का पद भी संभाला। चाय बागान के मालिक होने के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में उनका काफी राजनीतिक प्रभाव है। उनके इस्तीफे से भाजपा को असम में आगामी चुनावों में नुकसान उठाना पड़ सकता है।

असम में फिलहाल मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अगुवाई में भाजपा सरकार सत्ता में है और पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने का लक्ष्य रखती है। ऐसे में राजेन गोहेन और अन्य नेताओं का पार्टी छोड़ना भाजपा की राजनीतिक रणनीति और लोक समर्थन पर असर डाल सकता है।

करवा चौथ पर बाजारों में दिखी खास रौनक, महिलाएं तैयारियों में जुटी

(जीएनएस)। मुंबई। देशभर में करवा चौथ का पर्व आज (10 अक्टूबर 2025) बड़े उत्साह और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन हर विवाहित महिला के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि व्रत का संबंध पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य से जुड़ा होता है। इसी वजह से बाजारों में इस दिन खास रौनक देखने को मिलती है।

करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलती हैं। इस दिन महिलाएं दुल्हन की तरह सजती-संवरती हैं। लाल साड़ी, सिंदूर, चूड़ियां, बिंदिया, महावर और गहनों से सजी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। बाजारों में पहले से ही तैयारियां देखने को मिलीं। घरों में पूजा की थालियां सजाना, करवे खरीदना और सजावट की व्यवस्था कई दिन पहले से शुरू हो जाती है। मुंबई के भुलेश्वर के बाजारों में मेंहदी लगवाने और पारंपरिक चूड़ियां खरीदने के लिए महिलाओं की लंबी कतारें लगी थीं। मेंहदी कलाकारों की दुकानों पर भी सुबह से ही भारी भीड़ रही। वाराणसी, दिल्ली और कोलकाता में भी बाजारों में खास रौनक देखने को मिली। दुकानों में पारंपरिक करवे, पूजा की थालियां और श्रृंगार के सामानों की भरमार थी। इस बार मिट्टी और स्टील के डिजाइनर करवे विशेष आकर्षण का केंद्र बने। रंग-बिरंगे करवे और सुंदर सजी हुई थालियां महिलाओं को काफी पसंद आ रही हैं। व्यापारियों ने बताया कि पिछले सालों की तुलना में इस बार करवा चौथ के बाजार में अधिक रौनक और खरीदारी देखी जा रही है। इस बढ़ती खरीदारी से व्यापारियों के चेहरों पर मुस्कान दिखाई दे रही है। वहीं, महिलाएं पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ अपने प्रिय त्योहार की तैयारियों में पूरी तरह जुटी हुई हैं।

सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने वाले वकील पर कड़ी कार्रवाई

(जीएनएस)। नई दिल्ली में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट परिसर में हुए अभूतपूर्व घटनाक्रम के बाद, न्यायपालिका ने अपनी गरिमा और अनुशासन बनाए रखने का कड़ा संदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी. आर. गवई पर हमले की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर (71 वर्ष) की सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। एसोसिएशन ने कहा कि वकील का यह व्यवहार पेशेवर नैतिकता, न्यायिक आचरण और सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा के खिलाफ था। SCBA के सचिव ने जारी बयान में कहा कि "यह घटना न केवल न्यायालय की गरिमा पर प्रहार है, बल्कि पूरे वकालत पेशे की छवि को भी कलंकित करती है। बार एसोसिएशन ऐसे किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेगी जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सम्मान को ठेस पहुंचाए।" 6 अक्टूबर को हुई इस घटना में आरोपी वकील राकेश किशोर ने सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के दौरान अचानक CJI गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश की थी। हालांकि सुरक्षा कर्मियों की तत्परता के कारण जूता लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका और वकील को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। बताया गया कि उस वक्त चीफ जस्टिस की बेंच एक संवैधानिक महत्व के मामले की सुनवाई कर रही थी।

घटना के दौरान वकील ने नारेबाजी करते हुए कहा — "सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।" यह हंगामा कुछ ही क्षणों में पूरे कोर्टरूम में तनाव का माहौल बना गया, लेकिन जजों ने संयम बनाए रखा और कार्यवाही थोड़े अंतराल के बाद पुनः शुरू कर दी। घटना के बाद CJI बी. आर. गवई ने कहा, "हम उस पल बहुत हैरान थे, लेकिन अब यह सब बीती बात है। न्यायपालिका का काम प्रतिशोध नहीं, बल्कि न्याय है। हमें आगे बढ़ना है और देश की सेवा करनी है।" उनके इस बयान को न्यायिक गरिमा और उदार दृष्टिकोण का प्रतीक माना जा रहा है।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस उज्जल भुइयां ने इस घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि "यह सिर्फ चीफ जस्टिस पर हमला नहीं, बल्कि पूरे सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा पर हमला है। ऐसे कृत्य पर कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई इस तरह की हिमाकत न करे।" इस बीच, बेंगलुरु पुलिस ने आरोपी वकील राकेश किशोर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 132 और 133 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। यह एफआईआर ऑल इंडिया एडवोकेट एसोसिएशन की शिकायत पर की गई। हालांकि CJI गवई ने स्वयं वकील के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया। सूत्रों के अनुसार, आरोपी वकील का व्यवहार पिछले कुछ समय से विवादित रहा था। उसने कई बार कोर्ट में अनुचित भाषा का प्रयोग किया और न्यायिक अनुशासन का उल्लंघन किया था। एसोसिएशन ने पहले भी उसे चेतावनी दी थी, लेकिन उसने अपने रवैये में सुधार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों ने इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि "यह फैसला न्यायपालिका की मर्यादा की रक्षा के लिए आवश्यक था। अदालतें देश के न्याय और लोकतंत्र की नींव हैं, उन पर हमला सिर्फ किसी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि संस्थान पर होता है।"

अब जब आरोपी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है, और मामला पुलिस के पास है, यह घटना भारतीय न्याय व्यवस्था में अनुशासन और सम्मान की अहमियत को दोबारा रेखांकित करती है। जैसा कि CJI ने कहा — "हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन यह घटना एक चेतावनी है कि अदालत का सम्मान हर कीमत पर बनाए रखना ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा दायित्व है।"

पी चिदंबरम ने पीएम मोदी के 26/11 बयान को गलत बताया, कहा "संदर्भ तोड़ा-मरोड़ कर पेश किया गया"

(जीएनएस)। नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने गुरुवार को 26/11 मुंबई आतंकी हमलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को गलत बताते हुए खेद जताया। चिदंबरम ने X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि यह पढ़कर निराशा हुई कि प्रधानमंत्री ने काल्पनिक बातें उनके नाम से जोड़ दीं और उनके विचारों को गलत तरीके से पेश किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को मुंबई में कहा था कि कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने एक इंटरव्यू में यह दावा किया था कि मुंबई हमले के बाद भारतीय सेनाएं पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयार थीं और पूरा देश भी यही चाहता था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने आतंकियों के सामने घुटने टेके। पीएम ने सीधे चिदंबरम का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके 30 सितंबर के इंटरव्यू का हवाला दिया।

चिदंबरम ने कहा कि उनके कथन को संदर्भ से बाहर पेश किया गया और उनका उद्देश्य किसी सरकार या व्यक्ति पर आरोप लगाने का नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे केवल घटनाओं के ऐतिहासिक संदर्भ में अपनी बात रख रहे थे। यह बयान चिदंबरम ने 10 दिन बाद जारी किया और विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया के रूप में पेश किया।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बयान के बाद 26/11 हमलों को लेकर राजनीति और सार्वजनिक बहस दोनों तेज हो सकती हैं, क्योंकि दोनों दल इस मामले में अपने-अपने रुख को जनता तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के छह आर्थिक क्षेत्रों के 'क्षेत्रीय आर्थिक मास्टर प्लान' का अनावरण किया

▸▸ छह क्षेत्रीय मास्टर प्लान अंतर्गत 500 से अधिक परियोजनाओं में 15 लाख करोड़ रुपए (200 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक) से अधिक के सार्वजनिक एवं निजी पूंजी निवेश का आयोजन

▸▸ मुख्यमंत्री की गुजरात के क्षेत्रीय आर्थिक विकास से 'विकसित गुजरात, विकसित भारत' साकार करने की मंशा

▸▸ छह क्षेत्रों में उत्तर गुजरात, कच्छ, मध्य गुजरात, सौराष्ट्र, तटवर्ती सौराष्ट्र तथा सूरत शामिल

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात को देश का ग्रोथ इंजन बनाने एवं विकसित भारत@2047 के विजन में अग्रसर रहने के दृढ़ संकल्प के साथ गुरुवार को उत्तर गुजरात के मेहसाणा में आयोजित 'वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस' (वीजीआरसी) श्रृंखला की पहली कॉन्फ्रेंस में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।

श्री पटेल ने राज्य के छह मुख्य आर्थिक क्षेत्रों के लिए तैयार किए गए क्षेत्रीय आर्थिक मास्टर प्लान (रीजनल इकोनॉमिक मास्टर प्लान) का अनावरण व लोकार्पण किया। गुजरात के ऐतिहासिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इन छह मुख्य आर्थिक क्षेत्रों के लिए ये मास्टर प्लान तैयार किए गए हैं। इन क्षेत्रों में उत्तर गुजरात, कच्छ, मध्य गुजरात, सौराष्ट्र, तटवर्ती सौराष्ट्र तथा सूरत शामिल हैं।

ये मास्टर प्लान गुजरात के 33 जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था को वर्तमान 280 बिलियन डॉलर (वित्तीय वर्ष 2023) के कद से बढ़ाकर 3.5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक तक पहुँचाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने का रोडमैप हैं।

इन छह क्षेत्रीय मास्टर प्लान अंतर्गत 500 से अधिक परियोजनाओं में 15 लाख करोड़ रुपए (200 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक) से अधिक के सार्वजनिक एवं निजी पूंजी निवेश का आयोजन किया गया है। आर्थिक वृद्धि का लाभ युवाओं को मिले; यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में उद्योगों के सहयोग से रीजनल स्किलिंग सेंटर्स तथा सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस (ग्रीन स्किल्स, ब्लू इकोनॉमी, लॉजिस्टिक्स, एआई एकेडेमी आदि) स्थापित किए जाएंगे। इन योजनाओं तथा आर्थिक गतिविधियों द्वारा राज्य के युवाओं के लिए अनुमानित 280 लाख लाख नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

ये क्षेत्रीय मास्टर प्लान्स प्रत्येक क्षेत्र की स्थानीय उत्पादन क्षमताओं के अनुरूप फ्यूचरिस्टिक सेक्टर को लक्ष्य बनाएंगे :

▸▸ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग : इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), बैटरी स्टोरेज, मरीन केमिकल्स, बायोलॉजिक्स, औद्योगिक सिरामिक्स तथा बायोफ्यूल जैसे भावी क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा, जो मूल्यवर्धन तथा टेक्नोलॉजी आधारित नवीनता द्वारा संचालित होगा।

▸▸ सर्विस सेक्टर : 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 51 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य है। जीसीसी, क्लिनिकल रिसर्च, लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्ट डिजाइन तथा बैंकिंग, फाइनैंशियल सर्विसेज व बीमा (बीएफएसआई) जैसी नई सेवाओं द्वारा कुशल नौकरियों में वृद्धि होगी।

▸▸ पर्यटन : मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, हेरिटेज टूरिज्म, इको-टूरिज्म, क्रूज टूरिज्म तथा आध्यात्मिक व वेनलेस टूरिज्म जैसे नए मार्गों द्वारा पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।

▸▸ ब्लू इकोनॉमी : गुजरात के 2240 किलोमीटर लंबे समुद्र तट पर पोर्ट लॉजिस्टिक्स, शिप बिल्डिंग, फिश प्रोसेसिंग तथा निर्यात, समुद्री पर्यटन तथा मरीन इनोवेशन में निवेश द्वारा मछुआरा समुदाय को सशक्त बनाया जाएगा और नई नौकरियों का सृजन होगा।

▸▸ ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा टिकाऊ विकास : एग्रो प्रोसेसिंग एवं डेयरी उद्योग एग्रीटेक तथा उच्च मूल्य के उत्पादों (रेडी टु ईट फूड्स, न्यूट्रास्युटिकल्स, प्रोटीन सप्लिमेंट्स) पर ध्यान केन्द्रित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मूल्यवर्धन लाया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, सर्कुलर इकोनॉमी तथा ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग सस्टेनेबिलिटी के एजेंडा को आगे बढ़ाएंगे। इस विकास योजना के मूल में सुदृढ़ ढाँचागत सुविधाओं का विकास है। आगामी 22 वर्षों में कोस्टल रेलवे, हाईस्पीड अंतरराज्यीय रेल कॉरिडोर तथा सी-लिंक परियोजनाएँ लागू हंगी, एयरपोर्ट का विस्तार होगा और कार्यक्षम लॉजिस्टिक्स के लिए नए कारगो टर्मिनल तथा कोल्ड चेन स्थापित किए जाएंगे।

यहाँ उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने 19 जुलाई 2025 को गांधीनगर में गुजरात राज्य इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन (ग्रिट) के कार्यालय का उद्घाटन किया था। राज्य के क्षेत्रीय आधार पर आर्थिक विकास के जरिये विकसित गुजरात के विजन को साकार करने के लिए ग्रिट थिंक टैंक के रूप में कार्यरत है।

ग्रिट डेटा आधारित नीतिगत निर्णयों एवं विकास योजनाओं को वैज्ञानिक पद्धति से तैयार कर विकसित भारत@2047 के विजन में गुजरात को अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा।

पश्चिम बंगाल में एसआईआर से 1.2 करोड़ अवैध मतदाता हटने का दावा, टीएमसी ने जताई चिंता

(जीएनएस)। कोलकाता। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद शांतनु ठाकुर ने गुरुवार को दावा किया कि चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के माध्यम से राज्य की मतदाता सूची से लगभग 1.2 करोड़ अवैध मतदाता हटाए जा सकते हैं।

ठाकुर के इस दावे के बाद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। टीएमसी ने चेतावनी दी कि यदि एसआईआर के तहत मतदाता सूची में बदलाव किया गया तो इसका सबसे बड़ा नुकसान मतुआ शरणार्थियों को होगा। टीएमसी का कहना है कि यह प्रक्रिया संवैधानिक अधिकारों पर असर डाल सकती है और राजनीतिक रूप से वोटरों को भयभीत करने का प्रयास है।

राज्य में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग राज्य के अधिकारियों को धमका रहा है और उनकी पार्टी की निष्पक्ष चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है। केंद्रीय मंत्री ठाकुर के दावे और टीएमसी की प्रतिक्रिया के बीच पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सियासी टकराव और बढ़ गया है। विश्लेषकों का कहना है कि एसआईआर और मतदाता सूची में संभावित बदलाव से चुनावी रणनीतियों पर असर पड़ेगा और दोनों मुख्य राजनीतिक दल इसे लेकर अपने-अपने तर्क और दावे पेश कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने अभी इस संबंध में कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है।

संभाजीनगर मनपा चुनाव में शिवसेना दोनों गुटों के बीच सियासी जंग तेज

(जीएनएस)। संभाजीनगर। महाराष्ट्र की राजनीति में छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका चुनाव अब चुनावी रणभूमि बन चुका है, जहाँ शिवसेना के दोनों गुट—उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे—अपने-अपने प्रभाव का प्रदर्शन करने में जुटे हैं। शनिवार को उद्धव ठाकरे का संभाजीनगर दौरा प्रस्तावित था, जिसमें वे पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद, रोड शो और जनसभा आयोजित करने वाले थे। लेकिन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को ही दौरे का ऐलान कर राजनीतिक माहौल को और गरम कर दिया। शिंदे का उद्देश्य था कि ठाकरे को चुनावी मंच पर कोई बढ़त न मिले और अपने नेताओं के माध्यम से सत्तारूढ़ गुट की ताकत का पहले ही प्रदर्शन कर दिया जाए। दोनों गुटों ने संभाजीनगर मनपा पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव का महत्व भी इसलिए अधिक है क्योंकि संभाजीनगर मनपा मराठवाड़ा की सबसे बड़ी मनपा होने के साथ ही शिवसेना दोनों गुटों के जनाधार की परीक्षा भी मानी जा रही है। यहां राज्य सरकार में मंत्री संजय शिरसाट का प्रभाव शिंदे गुट के पक्ष में काम कर सकता है। पिछली बार शिवसेना (अविभाजित) ने मनपा चुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन फूट के दौरान मेयर नंदकुमार घोडेले शिंदे गुट में शामिल हो गए। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस चुनाव में संभाजीनगर का परिणाम न केवल मनपा स्तर पर, बल्कि पूरे मराठवाड़ा और राज्य की शिवसेना दोनों गुटों के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। दोनों पक्ष चुनावी ताकत दिखाने के लिए पूरी रणनीति और प्रचार अभियान को सक्रिय कर रहे हैं।

गगनयात्री श्री शुभांशु शुक्ला ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से भेंट की

(जीएनएस)। गांधीनगर : गगनयात्री तथा भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला ने गुरुवार को मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार भेंट की।

उत्तर गुजरात अंचल की मेहसाणा जिले के खेरवा स्थित गणपत विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित हो रही प्रथम वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) के पहले दिन सहभागी होने आए श्री शुक्ला श्री पटेल से मिले। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने श्री शुभांशु शुक्ला को उनकी गगनयात्रा की सफलता के लिए अभिनंदन दिया।